छपरौला गाजियाबाद को जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत आबंटित की गई राशि

3251. **श्रीमती कमला सिन्हा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरप्रदेश के गाजियाबाद जिले में छपरौला ग्राम सभा को जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा अब तक कितनी धन राशि आवंटित की गई है ;

(ख) छपरौला ग्राम सभा द्वारा योजना के अन्तर्गत क्या-क्या कार्य किये गये हैं ; और

(ग) क्या जिला प्रशासन ने योजना के अन्तर्गत किये गये कार्य का निरीक्षण किया है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) से (ग) जवाहर रोजगार योजना पूरे देश में लगभग 460 जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों और लगभग 2,20,000 ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों के स्वरूप और मात्रा के बारे में निर्णय भी इन्हीं निकायों द्वारा लिया जाता है । भारत सरकार न तो जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में विभिन्न ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा रखती है और न ही उन्हें आबंटित निधियों की केन्द्र स्तर पर निगरानी करती है ।

Agricultural researches by rural people

3252. SHRI VISHWASRAO RAMRAO PATIL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether there is any scheme under Government's consideration to patent the agricultural reserches done by rural people;

(b) whether the journal of Rural Development is published only in English and the rural people do not get the benefit of carrying out research work therefrom; and

(c) if so, the corrective measures proposed to be taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL) (a) No, Sir.

(b) The Journal of Rural Development is a bi-monthly by National Institute of Rural Development (NIRD) published in English. In addition the Institute publishes the bi-annual Hindi version 'Grameen Vikas Sameeksha' in January and July each year, with original contributions on research in the area of rural development. NIRD also brings out on annual basis 'Research Highlights' both in English and Hindi. These journals reach large sections of Government functionaries, non-governmental organisations and individuals engaged in research work on rural development and they are found to be quite useful.

(c) Does not arise.

Schemes for rural employment

3253. SHRI PASUMPON THA. KIRUTTINAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the details of various schemes introduced for rural employment during the Seventh Five Year Plan period and achievements thereof upto March, 1992;

(b) whether it is a fact that the Employment Guarantee Scheme in force in Maharashtra was not adopted by other States during the above said period; and

(c) if so, what steps taken/proposed to be taken for emphasising for adoption of the scheme by other States during Eighth Five Year Plan?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL): (a) The major Rural Employment Programmes that were implemented during the Seventh Five Year Plan were National Rural Employment Programme (NREP), Rural Landless Employment Guarantee Programme (RLEGP) and Jawahar Rozgar Yojana (JRY). In the 5th year of the Seventh Five Year Plan i.e. 1989-90, NREP and RLEGP were merged into a single Rural Employment

Programme known as JRY. The progress under Rural Employment Programmes are monitored in terms of mandays of employment generated. As per reports received from the States/UTs, 51833.12 lakh mandays of employment have been generated upto March, 1992 under these programmes.

(b) Yes, Sir.

(c) Removal of poverty and unemployment have, for many years, formed the crucial component of our strategy for growth, social justice and equity. The importance of employment programmes in reducing rural poverty is reflected in the Seventh Five Year Plan which continues to be the main objective during the Eighth Five Year Plan also. State Governments will be requested to take up more and more rural employment schemes during the Eighth Plan period and reach a stage of providing employment guarantee over a period of time.

भूमि सुधार कानूनों का विफल कार्यान्वयन

3254. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा अधिनियमित भूमि सुधार कानून सफल सिद्ध नहीं हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) गत वर्ष के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा भूमि सुधारों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे तथा इनमें से प्रत्येक लक्ष्य के संबंध में कितनी प्रगति की जा सकी ।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) और (ख) यह कहना सही नहीं है कि सरकारों द्वारा बनाए गए भूमि सुधार कानून सफल सिद्ध नहीं हुए हैं । विभिन्न भूमि सुधार उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के फलस्वरूप बिचौलिया काश्तकारियों को समाप्त करके 20 मिलियन कृषकों को राज्य के सीधे संपर्क में लाया गया । 110.40 लाख कृषकों को 247.06 लाख एकड़ से अधिक भूमि पर सुरक्षित काश्तकारी के अधिकार दिए गए थे। फालतू घोषित की गई 72.62 लाख एकड़ भूमि में से 49.56 लाख एकड़ भूमि 47.25 लाख लाभार्थियों में वितरित की गई है । 1493.74 लाख एकड़ भूमि की चकबन्दी की गई थी। 21 जिलों में प्रायोगिक आधार पर भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण किया गया है । इस दिशा में प्रयास जारी है ।

(ग) अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के वितरण के अलावा, भूमि सुधार उपायों के प्रत्येक पहलू के लिए मात्रा संबंधी लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं । 1991–92 के दौरान 119270 एकड़ भूमि के वितरण के लक्ष्य की तुलना में 154067 एकड़ भूमि का वितरण किया गया है जो कि वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य को पार कर गया है ।

मेघवन में सड़क का निर्माण

3255. **श्री मौलाना असद मदनी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत मेघवन गांव में सड़क के निर्माण के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल): जवाहर रोजगार योजना पूरे देश में लगभग 460 जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों और लगभग 2,20,000 ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है । जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों के स्वरूप और मात्रा के बारे में निर्णय भी इन्हीं निकायों द्वारा लिया जाता है। भारत सरकार जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में विभिन्न जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों और ग्राम पंचायतों द्वारा